REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत वित्त का प्रवाह व भूमिका

ममता कुमारी
शोध छात्रा, तिलका मांझी , भागलपुर, विश्वविद्यालय.

सारांश

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग दो तिहाई जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्रक की राष्ट्रीय आय में भागीदारी लगभग 19प्रति0 है। कृषि में वृद्धि के लिए वित्त की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। कृषि क्षेत्र को उपलब्ध वित्त न केवल कम दरो पर उपलब्ध हो बल्कि सही समय व उचित मात्रा में भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने समय–समय पर नीतियाँ बनाई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग गरीब है, उनकी आय कम है, इसलिए उनकी बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण पर्याप्त मात्रा में निवेश की कमी है। इसलिए ग्रामीण कुशल वित्त व्यवस्था का होना आवश्यक पहलू है। संस्थागत वित्त व्यवस्था, ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह किसानों को साहूकारों से मुक्त कराती है तथा कम दर व उचित समय पर ऋण मुहैया कराती है। ग्रामीण वित्त व्यवस्था में संस्थागत वित्त व्यवस्था का महत्व उदारीकरण के बाद और भी ज्यादा बढ गया है। भारत में संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए बहुएजेंसी व्यवस्था का सहारा लिया गया जिसमें मुख्यतः को–ऑपरेटिव बैंक, व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक प्रमुख है।

परिचय :–

कृषि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि समय–समय पर कृषि और गैर–कृषि कार्यो में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पडते है। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा रहता है।

स्वतंत्रता से पूर्व तक संस्थागत वित्त संस्थाओं के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महाजनों व व्यापारी वर्ग का वर्चस्व था। वे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से ऊँची दर पर ब्याज वसूलते थे जिससे वे ऋणग्रस्तता के दुश्चक्र से मुक्त नहीं हो पाते थे। देश में 1969 में 14 बडे वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् संस्थागत वित्त का समुचित प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में भी संभव हो पाया है। ग्रामीण साख आवश्कताओं की पूर्ति के लिए बहु–संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) की स्थापना 1982 में की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है।

संस्थागत वित्त की भूमिका :–

वर्त्तमान परिदृश्य में ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु–एजेंसी संस्थान जैसे, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी तथा भूमि विकास बैंकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। ये सस्ती ब्याज दरो पर ग्रामीणों को उनके व्यवसाय व कृषि कार्यो हेतु ऋण की

पर्याप्त पूर्ति करती है। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए ''स्वयं सहायता समूहों'' (एस0एच0जी0) का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूरी तरह समन्वित साबित हुई है। चूंकि इसके लिए एक बडे ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्य ग्रामीण परिवारो का एक बडा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययिता की भावना बढाता है।

इस प्रकार एकत्रित राशि का प्रयोग जरूरतमंद सदस्यों द्वारा ऋण के रूप में की जाती है। ऋण की राशि आसान किस्तों में लौटाई जाती है और वो भी उचित ब्याज दर पर। नावार्ड के अनुमान के अनुसार वर्त्तमान में देश भर में 2.2 मिलियन SHG देश के अनेक भागों में कार्य कर रहे है जो गरीबों को खासकर महिलाओं की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वयं सहायता समूह का यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, अलग–अलग क्षेत्र और व्यवसायों से जुडा हुआ है। सरकार उन्हें आगे बढाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक मदद और अवसर भी उपलब्ध करवा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों की एकीकृत व तीव्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण ऋण की व्यवस्था में नावार्ड ने सराहनीय कार्य किए है। नावार्ड कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने, वाणिज्यिक, सहकारी व क्षेत्रीय बैंकों को पुर्नवित व वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थागत ऋण व्यवसाय का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसके अतिरिक्त नावार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। इस संस्थान के कंधो पर सहकारी ऋण संस्थाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी की जिम्मेदारी भी है।

किसानों की आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों व सहकारी संस्थाओं को मार्गदर्शन व वित्त प्रदान करने में नावार्ड ने वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी नवोन्मेषी योजना का सूत्रपात किसानों को बैंक ऋण समय पर प्रदान करने तथा ऋणों में अधिक लचीलापन लाने हेतु किया है।

इस संस्थान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोग हेतु शहरी क्षेत्रों से धन जुटाने की व्यवस्था की जाती है। नावार्ड बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को लधु, मध्यम तथा दीर्धावधि ऋण प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नावार्ड के द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवकों में क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन हेतु 'आरईडीपी' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

ई–गवर्नेस, ई–मेल जैसी सुविधाओं से गांवो को लैस करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वित रूप से सामान्य केन्द्रो की स्थापना में योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु अनुदानो और उदार ऋणों की व्यवस्था करने हेतु नावार्ड ने अनेक प्रकार के विशेष उद्वेश्य केन्द्रित कोष स्थापित किए है। इस प्रकार से नावार्ड वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार स्टजन, महिला विकास, सूक्ष्म वित्त संस्थानो तथा स्वयंसहायता समूहो के विकास, गांवो में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए गांवो को विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने का प्रयास कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहकारी संस्थाओं व बैंको की भूमिका उत्तरोतर बढती जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्णजमंती स्वरोजगार कार्यक्रम व स्वयंसहायता समूहो के माध्यम से सरकार महिलाओं व पिछडी जातियों व वर्गो हेतु 'वित्तीय व्यवस्था' का प्रावधान करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्प है। इस उद्वेश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार हेतु बैंकों के द्वारा उद्वार शर्तो पर ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है तथा साथ ही ''राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान' के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। निःसदेह रूप से देश में सार्वजनिक क्षेत्र संकुचित होते हुए भी ''रोजगार कार्यक्रम'' बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार प्रदत्त करने में लाभप्रद साबित हो सकता है बशर्ते बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों व सहकारी संस्थाओं का इस योजना के क्रियान्वयन में यथोचित सहयोग व निर्देश हो।

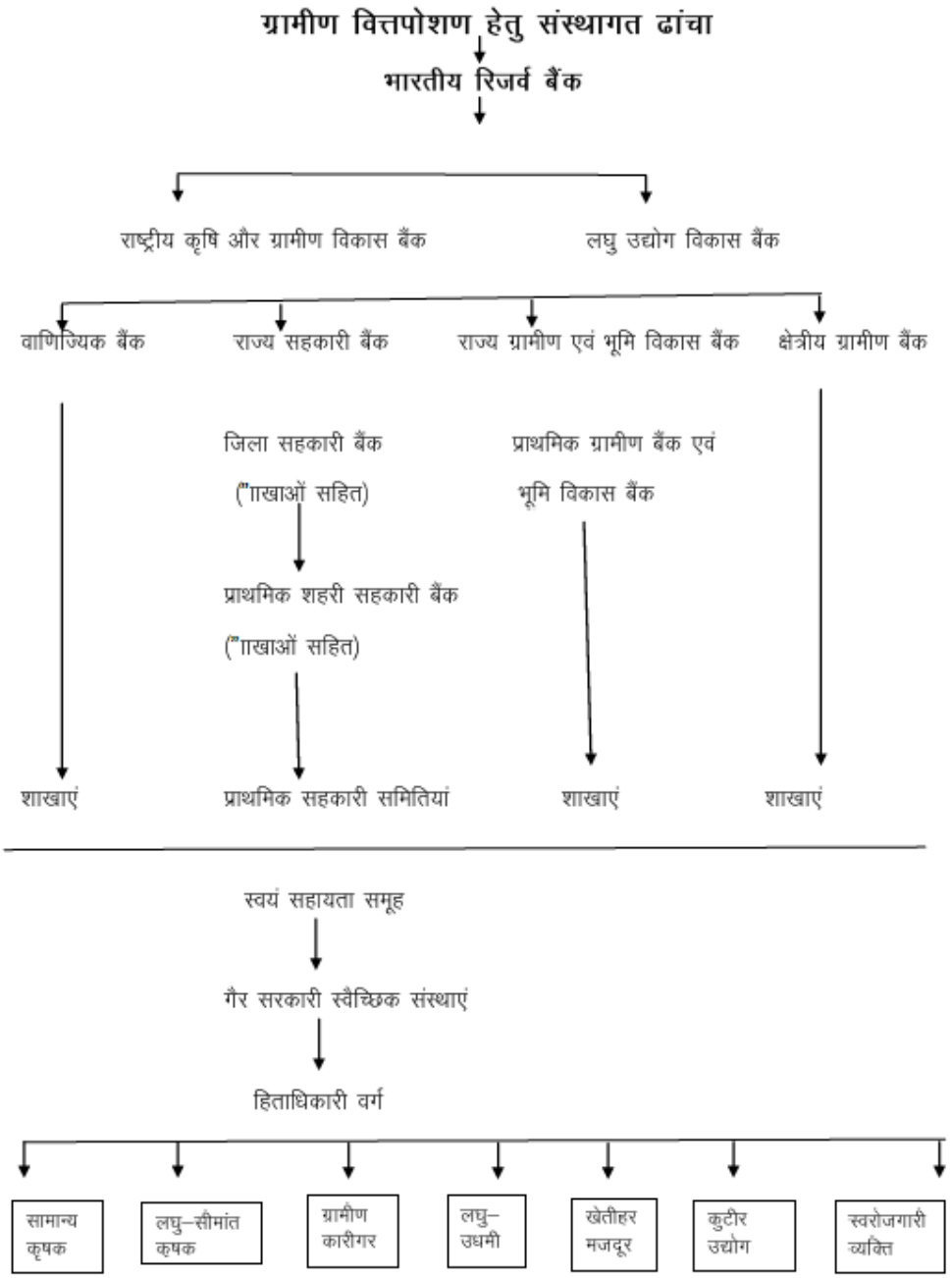

ग्रामीण संस्थागत वित्त स्त्रोतः एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पडा है, विशेषतः हरित क्रांति के सफलता के पश्चात् से किसानों को साख सेवाएं और सुविधाएं देने तथा उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के वित्तीय सुविधाओं को इन तक सुलभ बनाया है। देश में अब अकाल की स्थिति 'बीते जाने की बात' हो गई है। हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुंच चुके है कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे है। किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है।

संभवतः व्यापारिक बैंको को छोडकर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पायी है। न ये सही ऋण चाहने वालो को ऋण दे पाती है और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या अत्यंत ही चिंतनीय है।

अतः किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे है? स्पष्ट है कि किसान बडे पैमाने पर ऋण अदा करने से इंकार कर रहे है। इसका क्या कारण हो सकता है?

अतः इसके लिए आवश्यक है कि बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि वे ऋण देने वाले और ऋण लेने वालों के बीच में एक सेतु का कार्य करें। उन्हें ग्रामीण कृषकों में मितव्ययिता के प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय स्रोतो का कुशलतम प्रयोग कर सके।

संदर्भ सूची :–

1. http://www.rbi.org.in
2. रोल ऑफ नावार्ड इन रूरल ट्रांसफॉरमेशन, Lap Lambert Academic- publishing, ISBN: 9783659365225, 365936522x
3. किसान खेती, वर्ष –1, अंक – 3, (जूलाई–सितम्बर), 2014
4. ग्राम विकास कार्यक्रम, Gullybaba Publishing House Pvt. Ltd, January 2018, ISBN 10-938392148x, ISBN-13-978-9383921485

ममता कुमारी
शोध छात्रा, तिलका मांझी , भागलपुर, विश्वविद्यालय.

LBP PUBLICATION